SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, the rise in the price of petrol and diesel ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I request the hon. Members to resume their seats ...(Interruptions)...

Please raise this subject at an appropriate time...(Interruptions)... Question No. 1 please...(Interruptions)...

श्री वीरेन्द्र भाटियाः सर, महात्मा गांधी जी को, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the Question Hour to proceed. ... (Interruptions)...

श्री वीरेन्द्र भाटियाः सर, एक मिनट के लिए। ...(व्यवधान)... सर, वहां राष्ट्रपिता का, ...(व्यवधान)... उनका अपमान हो रहा है और आप कहते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठे रहें।

MR. CHAIRMAN: Please raise this at appropriate time and allow the Question Hour to proceed. Question No. 1 please. ... (Interruptions)...

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): सर, सदन की अवहेलना हो रही है। आज से सेशन है और सरकार ने एक दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल का दाम बढा दिया है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the Question Hour to proceed. ... (Interruptions)...

श्री वीरेन्द्र भाटियाः सर, क्या राष्ट्रपिता के सम्मान के लिए हम लोग यहां पर कह नहीं सकते? सर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)... राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the Question Hour to proceed. ...(Interruptions)... Please Mishraji. ...(Interruptions)... No; no, this is not the time for raising. ...(Interruptions)... Please allow the Question Hour to proceed. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रः सर, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे अपमान तो यह कर रहे हैं। ..(व्यवधान)... जिस तरह का व्यवहार यह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to allow the Question Hour to proceed. Please allow the Question Hour to proceed. Question No. 1.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### राज्यों में दलित जनसंख्या

\*1. श्री राम जेठमलानीः श्री शिवानन्द तिवारी:††

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में दलित जनसंख्या का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है;
- (ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में दलित जनसंख्या का प्रतिशत कितना-कितना है;

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।

- (ग) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है; और
- (घ) यदि हां, तो वर्ष 2004 से वर्ष 2008 की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसी कुल कितनी घटनाएं हुईं जिनमें दलित प्रभावित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (मुकुल वासनिक): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

# विवरण

- (क) और (ख) राज्य/संघ राज्यवार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता भिन्न-भिन्न है और इसे संलग्न विवरण-। में दिया गया है। (नीचे देखिये)
- (ग) वर्ष 2004 से 2008 के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रति किए गए अपराधों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण-॥ में दी गई है। (नीचे देखिये)
- (घ) 2004-2008 के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण-॥ में दी गई।

*विवरण*-। 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशतता का ब्यौरा

क्रम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सं.	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता
1 2	3
।. राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	16.2
2. अरुणाचल प्रदेश	0.0
3. असम	6.8
4. बिहार	15.7
5. गोवा	1.8
6. गुजरात	7.1
7. हरियाणा	19.3
8. हिमाचल प्रदेश	24.7
9. जम्मू और कश्मीर	7.6
10. कर्नाटक	16.2

1 2	3
11. केरल	9.8
12. मध्य प्रदेश	15.2
13. महाराष्ट्र	10.2
14. मणिपुर	2.8
15. मेघालय	0.5
16. मिजोरम	0.03
17. नागालेंड	0
18. उड़ीसा	16.5
19. पंजाब	28.9
20. राजस्थान	17.2
21. सिक्किम	5.0
22. तमिलनाडु	19.0
23. त्रिपुरा	17.4
24. उत्तर प्रदेश	21.1
25. पश्चिम बंगाल	23.0
26. छत्तीसगढ़	11.6
27. झारखंड	11.8
28. उत्तराखंड	17.9
॥. संघ राज्य क्षेत्र	
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0
30. चंडीगढ़	17.5
31. दादरा और नागर हवेली	1.9
32. दमन और दीव	3.1
33. दिल्ली	16.9
34. लक्षद्वीप	0.0
35. पुडुचेरी	16.2
भारत	16.2

विवरण-॥

वर्ष 2004 से 2008 के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें पीड़ित अनुसूचित जातियों से संबंधित थे
2004	26522
2005	25836
2006	26665
2007	29825
2008	२४९७७ (अनन्तिम)

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

# विवरण-॥।

2004-2008 के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004 से 2008 के दौरान दर्ज किए गए अनुसूचित जातियों
सं.		से संबंधित मामलों की कुल संख्या
1	2	3
I.	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	16300
2.	अरुणाचल प्रदेश	02
3.	असम	716
4.	बिहार	11398
5.	छत्तीसगढ़	2458
6.	गोवा	14
7.	गुजरात	5779
8.	हरियाणा	1207
9.	हिमाचल प्रदेश	377
10.	जम्मू और कश्मीर	-
11.	झारखंड	1435
12.	कर्नाटक	8300

1 2	3
13. केरल	2099
14. मध्य प्रदेश	20774
15. महाराष्ट्र	4630
16. मणिपुर	0
17. मेघालय	0
18. मिजोरम	0
19. नागालैंड	0
20. उड़ीसा	5345
21. पंजाब	685
22. राजस्थान	19555
23. सिक्किम	40
24. तमिलनाडु	6363
25. त्रिपुरा	66
26. उत्तर प्रदेश	25576
27. उत्तराखंड	516
28. पश्चिम बंगाल	57
॥. संघ राज्य क्षेत्र	
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30. चंडीगढ़	05
31. दादरा और नागर हवेली	05
32. दमन और दीव	04
33. दिल्ली	104
34. लक्षद्वीप	0
35. पुडुचेरी	09
कुल	133819

स्रोत:- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी:- (i) अत्याचार निवारण अधिनियम, जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

(ii) कालम 3 में दी गई संख्या में वर्ष 2008 के अस्थायी आंकड़े शामिल हैं।

(iii) उड़ीसा के लिए 2008 की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

#### Dalit population in States

†\*1. SHRI RAM JETHMALANI: SHRI SHIVANAND TIWARI:††

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the dalit population in the country vary in percentage in different States;
  - (b) if so, the percentage of dalit population in each State;
- (c) whether it is also a fact that the incidents of atrocities on dalit have been on the rise over the years; and
- (d) if so, the number of total incidents that have taken place during the period 2004 to 2008 in each State wherein the dalits have been affected?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

#### Statement

- (a) and (b) The details of State/Union Territory-wise percentage of Scheduled Castes population to total population varies and is given in the enclosed Statement-I. (See below)
- (c) The number of offences committed against members of Scheduled Castes, registered by the Police under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, year-wise, during the years 2004 to 2008, are given in the enclosed Statement-II. (See below)
- (d) The State/Union Territory-wise total number of offences committed against members of Scheduled Castes, during 2004 to 2008, registered by the Police under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, are given in the enclosed Statement-III.

# Statement-I

Details of State/Union Territory-wise percentage of population of Scheduled Castes to their total population, as per 2001 Census

SI.	State/UT	Percentage of SC population to
No		total population
1	2	3
I.	States	
1.	Andhra Pradesh	16.2
2.	Arunachal Pradesh	0.6
3.	Assam	6.8
4.	Bihar	15.7

<sup>†</sup>Original notice of the question was received in Hindi.

<sup>††</sup>The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

1 2	3
5. Goa	1.8
6. Gujarat	7.1
7. Haryana	19.3
8. Himachal Pradesh	24.7
9. Jammu and Kashmir	7.6
10. Karnataka	16.2
11. Kerala	9.8
12. Madhya Pradesh	15.2
13. Maharashtra	10.2
14. Manipur	2.8
15. Meghalaya	0.5
16. Mizoram	0.03
17. Nagaland	0
18. Orissa	16.5
19. Punjab	28.9
20. Rajasthan	17.2
21. Sikkim	5.0
22. Tamil Nadu	19.0
23. Tripura	17.4
24. Uttar Pradesh	21.1
25. West Bengal	23.0
26. Chhattisgarh	11.6
27. Jharkhand	11.8
28. Uttarakhand	17.9
II. Union Territories	
29. Andaman and Nicobar Islands	0.0
30. Chandigarh	17.5
31. Dadra and Nagar Haveli	1.9
32. Daman and Diu	3.1
33. Delhi	16.9
34. Lakshadweep	0.0
35. Puducherry	16.2
India	16.2

Statement-II

Number of offences committed against members of Scheduled Castes, registered by Police under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, year-wise, during the years 2004 to 2008

Year	Number of cases, where victims were SCs
2004	26522
2005	25836
2006	26665
2007	29825
2008	24971 (Provisional)

Source: National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs.

## Statement-III

State/Union Territory wise, total number of offences committed against members of Scheduled Castes, registered by Police under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, during 2004 to 2008

Sr.	State/UT	Total number of cases, concerning SCs,
No.		registered during 2004 to 2008
1	2	3
l.	States	
1.	Andhra Pradesh	16300
2.	Arunachal Pradesh	02
3.	Assam	716
4.	Bihar	11398
5.	Chhattisgarh	2458
6.	Goa	14
7.	Gujarat	5779
8.	Haryana	1207
9.	Himachal Pradesh	377
10	Jammu and Kashmir	_
11.	Jharkhand	1435
12.	Karnataka	8300
13.	Kerala	2099
14.	Madhya Pradesh	20774

1 2	3
15. Maharashtra	4630
16. Manipur	0
17. Meghalaya	0
18. Mizoram	0
19. Nagaland	0
20. Orissa	5345
21. Punjab	685
22. Rajasthan	19555
23. Sikkim	40
24. Tamil Nadu	6363
25. Tripura	66
26. Uttar Pradesh	25576
27. Uttarakhand	516
28. West Bengal	57
II. Union Territories	
29. Andaman and Nicobar Islands	0
30. Chandigarh	05
31. Dadra and Nagar Haveli	05
32. Daman and Diu	04
33. Delhi	104
34. Lakshadweep	0
35. Puducherry	09
TOTAL	133819

Source: National Crime Record Bureau, Ministry of Home Affairs.

Note: (i) The POA Act does not extend to Jammu and Kashmir

- (ii) The figures in column 3 include provisional data for year 2008.
- (iii) The figures for Orissa for 2008 are not yet available.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। सर, इसी सदन में इसी तरह के सवाल के जवाब में 2 दिसंबर, 2004 को सरकार ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2002 तक देश भर में जो हरिजन एट्रोसिटीज के मामले हुए थे, उनके बारे में बताया था, जिसके अनुसार वर्ष 1998 में 25,638 मामले दर्ज हुए थे, वर्ष 1999 में 25,093 मामले दर्ज हुए थे, वर्ष 2000 में 25,455 मामले दर्ज हुए थे और वर्ष 2002 में 33,560 मामले दर्ज हुए थे। सरकार ने अब जो आंकड़ा पेश किया है, वह लगभग उसी से मिलता जुलता है।

**श्री सभापति**: आप सवाल पूछें।

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, यह स्पष्ट करता है कि सारे प्रयासों के बावजूद जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति है, उसके विरुद्ध अपराध की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में दलित अत्याचार रोकने के लिए सरकार कौन सा विशेष उपक्रम, कौन सी विशेष कोशिश कर रही है?

SHRI MUKUL WASNIK: Mr. Chairman, Sir, I do appreciate the concern that the hon. Member has expressed while raising the issue of atrocities against the Scheduled Castes. He has pointed out that in December, 2004, there was an elaborate discussion in this House; but, subsequently, there has been no improvement in the situation. I think, the Government of the day had taken up the matter extremely seriously and it was as a follow up to that discussion that an Inter-State Council Meeting was held. The hon. Prime Minister had presided over the meeting. Here, I would like to quote what the hon. Prime Minister had mentioned in that meeting, "Continuing atrocities against the weaker sections of the society are a matter of national disgrace in a civilized society." We further elaborated, "Legislations alone are not sufficient in dealing with social violence. There must be a compassion for the victim and a firm resolve to deal with the perpetrator of these crimes. What is needed is a political will to eliminate such atrocities; a will to impose law; a will to ensure easy access to the police and justice system to the vulnerable sections". Apart from the Inter-State Council Meeting, there was a Committee set up under the Chairpersonship of the then Minister for Social Justice and Empowerment. We took up various issues with the State Governments. A meeting of the Secretaries, concerned with the social welfare, was also convened. But I would like to stress here that, like what the Hon'ble Prime Minister had mentioned, legislation alone will not be sufficient, there has to be a political will and in letter and spirit, the legislation which is there today needs to be implemented. I think, if we are able to do that at every level, the situation will change.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापित महोदय, मेरा मानना है कि सरकार इस मामले पर भाषण देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। यहीं बगल में, उत्तर प्रदेश में कल-परसों के अखबार में खबर छपी है कि वहाँ पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रधान के पद के लिए पांच बार चुनाव कराने की कोशिश हुई। लेकिन वहाँ जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके डर से किसी ने नॉमिनेशन तक फाइल नहीं किया। छठे दफे चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी आश्वस्त नहीं है कि कोई नॉमिनेशन भर पायेगा या नहीं। यह हालत है। इसके अलावा, आपकी जो थ्री-टायर पंचायती राज व्यवस्था है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

श्री शिवानन्द तिवारी: वहाँ जो आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के लोग जीत रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है, उनको शपथ तक नहीं लेने दी जाती है। ऐसी हालत है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अभी दिलत मुख्य मंत्री हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पृछ लें।

श्री शिवानन्द तिवारी: वहाँ पांच परसेंट राइज दलित के अगेन्स्ट में हुआ है। यह खबर अखबारों में छपी है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ लुब्बे लुबाब कहा, उसको ठोस रूप से कार्यान्वित कैसे किया जाएगा. इसकी सरकार के पास क्या योजना है. वह हम जानना चाहते हैं? श्री मुकुल वासनिक: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि यह बड़ा गंभीर मामला है। यह सिर्फ एक जगह हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की घटना होती है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए वहाँ पर अनुकूल वातावरण नहीं है, तो यह चिन्ता का विषय है। हम प्रदेश सरकार से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसके बारे में क्या किया गया है? लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)...

श्री शिवानन्द तिवारी: यु0पी0 में पांच परसेंट बढ गया, आप सरकार से क्या जानकारी लीजिएगा।

श्री मुकुल वासनिक: मैं समझता हूँ कि 2008 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जो आंकड़े बाद में आये हैं, वे आंकड़े भी हमने इसके जवाब में दे दिये हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि आंकड़े कितने हैं, इससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि आज भी इस तरह के अत्याचार होते हैं। हम इस विवाद में न पड़ें कि किसी एक प्रदेश में अत्याचार के अधिक मामले दर्ज होते हैं और दूसरे में कम होते हैं। अगर कहीं पर एक भी अत्याचार की घटना होती है तो मैं समझता हूँ कि वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यह विषय किसी तरह से राजनीति का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इससे ऊपर उठकर इसमें से रास्ता निकालने की आवश्यकता है। जो कमेटी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में पहले बनी थी, उसने देश भर में आठ मिटिंग्स की। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जोनल मिटिंग्स से हटकर अब हम एक-एक प्रदेश सरकार के साथ बैठकर यह चर्चा करें कि वे अत्याचार कम करने की दिशा में क्या उपाय कर रहे हैं?

SHRI D. RAJA: Sir, it is true that there must be a political will at all levels, but, at the same time, legislations are very important. The current Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules 1995 have a lot of inadequacies. The National Human Rights Commission headed by Justice A.S. Anand, in its report submitted in the year 2002, proposed several recommendations. The National Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has also proposed several amendments. There are many organisations and well-meaning democratic sections in this country which have demanded that there must be exclusive special courts, exclusive special public prosecution to address the increasing atrocities on dalits.

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI D. RAJA: I am coming to that, Sir. And, there are certain atrocities which have not been included in the Act such as practices like social boycott, economic boycott, social blackmail and economic blackmail.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI D. RAJA: Sir, my concrete question is, whether the Government is thinking to amend the existing legislations in order to strengthen these legislations to curb the increasing atrocities on Dalits.

SHRI MUKUL WASNIK: Mr. Chairman, Sir, I do agree with the hon. Member on the suggestion of setting up of exclusive special courts. There have been States which have already started working in this direction. Nine States have already appointed exclusive special courts so far to deal with the situation.

Sir, as far as amending the Act is concerned, at this point of time, the Government has no such proposal.

SHRI JESUDASU SEELEM: Sir, I would like to compliment and congratulate the hon. Minister for his new initiatives in curbing the atrocities on Dalits.

But, Sir, if you take the macro picture, the atrocities are on the high. However, the conviction rate is almost zero. The Cabinet Committee on Dalit Affairs, among other things, have suggested a series of measures to make this effective.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI JESUDASU SEELEM: So, part(a) of my question is, what are the steps taken by the Government?

Part(b) of my question is this. Sir, recently, the Cr.P.C. was amended regarding the offences which attract seven years' imprisonment. In those cases, the SHO should not make an arrest unless he records the evidence.

MR. CHAIRMAN: Please, raise the question.

SHRI JESUDASU SEELEM: Sir, this is a very, very important thing. We are pleading for exempting the cases pertaining to atrocities on Dalits from this amendment, because, in all the cases, the Police are not arresting the accused. So, this is leading to proliferation of crime. So, please take a note of this.

MR. CHAIRMAN: Are you asking a question?

SHRI JESUDASU SEELEM: Sir, I would request the Minister to clarify whether the Government is seriously thinking of exempting the crimes regarding the atrocities on Harijans from the amended provision of Cr.P.C.

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, as far as the hon. Member's comment regarding the conviction rate is concerned, we have authentic information that there are a few States where the conviction rate can be termed to be close to the national average as far as conviction in regard to cases filed under the IPC is concerned.

On the question whether we are going to exclude them, I think, I will have to collect information on this and I will provide it to the hon. Member.

श्री कृष्ण लाल बाल्मीिक: सभापित महोदय, मैं इसी संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि आज भी अनुसूचित जाति में बाल्मीिक और सफाई कर्मचारियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है। इस संदर्भ में हाल में राजस्थान की दो घटनाएं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी-अभी जयपुर के पास एक कूकश ग्राम है, जिसमें सवर्ण जाति के लोगों ने बाल्मीिक समुदाय के व्यक्तियों को उनके मकानों से बेदखल करके उनके मकानों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह 26.06.09 को जिला करोली में खोहरा ग्राम में बाल्मीिक समाज के व्यक्तियों के साथ ....

श्री सभापतिः आप प्रश्न पृछिए।

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि: सरकारी पानी की टंकी से पानी भरने पर मार-पीट की गई और जाति सूचकांक शब्द का उपयोग किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इन वर्गों के लोगों की स्वतंत्रता पर सरकार क्या कर रही है? क्या डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब का यही सपना था? देश स्वतंत्र हो गया ....

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए, प्लीज़।

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि: मेरा सवाल है कि आज इन वर्गों के लोगों की स्वतंत्रता पर सरकार क्या कर रही है? क्या डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब का यही सपना था?

श्री मुकुल वासनिक: चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने विशेष रूप से बाल्मीिक समाज के अधिकारों और उनकी परेशानियों के बारे में यहां पर ज़िक्र किया है। मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों में बाल्मीिक समाज ही एक ऐसा समाज है कि जिसको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का प्रयास, विशेष रूप से बाल्मीिक समाज के सामने जो परेशानियां हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, उन पर अलग-अलग दिक्कतों का जो बोझ है, वह बोझ किस तरह से कम किया जा सकता है, उस दिशा में जारी है।

#### 3G spectrum auction

\*2. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:††

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

- (a) whether Department of Telecom (DoT) has decided to refer 3G spectrum auction to the new Government for taking a final decision;
- (b) whether allocation has been a bone of contention between Government and mobile operators;
- (c) if so, whether with this decision of referring the spectrum issue to new Government, the country's top three GSM operators, *viz.* Bharti Airtel, Vodafone Essar and Idea Cellular, have saved around Rs. 4000 crore in the current financial year because of delay of DoT in this regard; and
  - (d) if so, by when Government would take a final decision for allocation of 3G spectrum?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

# Statement

- (a) and (b) In view of differences between TRAI and DoT on a number of issues such as number of blocks of spectrum to be auctioned, reserve price for spectrum and annual administrative charge, it has been decided to refer the matter to the Empowered Group of Ministers.
  - (c) and (d) Do not arise as the auction of 3G spectrum has not taken place.
- DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, this is a very important question. I must compliment the Government for making all efforts to raise Rs. 25-40,000 crores of revenue from auctioning the 3G spectrum. In this connection, various news items have been appearing in the newspapers, saying that the final auction is likely to take place in July, October or December. I would like to have a categorical clarification in reply from the hon. Minister as to how he is planning to do things as early as possible in order to save more revenue for the Government.

<sup>††</sup>The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.